

न्यूज़ टुडे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 को मंजूरी प्रदान की

जनगणना 2027 देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद आयोजित होने वाली 8वीं जनगणना होगी।

जनगणना 2027 के मुख्य विवरण

- चरणबद्ध संचालन: यह अभ्यास निम्नलिखित दो चरणों में होगा:
 - अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकान सूचीकरण और आवास गणना; तथा
 - फरवरी 2027 तक जनसंख्या प्रगणना (Enumeration)।
- प्रथम डिजिटल जनगणना: मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा।
- जातिगत डेटा: जनसंख्या प्रगणना चरण के दौरान जातिगत डेटा को भी दर्ज किया जाएगा।
- नई तकनीक: प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक समर्पित जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल विकसित किया गया है।
 - सेंसस-एज़-ए-सर्विस (CaaS): यह मंत्रालयों को स्पष्ट, मशीन द्वारा पढ़ा जा सकने वाला और कार्रवाई-योग्य प्रारूप में डेटा प्रदान करेगा।
- सहभागिता: जनता को स्व-प्रगणना का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

भारत में जनगणना के बारे में

- उत्पत्ति: पहली गैर-समकालिक जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी।
- आयोजक: गृह मंत्रालय के तहत भारत का रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय।
- वैधानिक अधिदेश (Statutory Mandate): जनगणना अधिनियम, जिसे 1948 में अधिनियमित किया गया था। यह जनगणना के संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- मानदंड: एकल किए गए डेटा में जनसांख्यिकी, आवास की स्थिति, धर्म और साक्षरता सहित विभिन्न मानदंड शामिल होते हैं। गांव या वार्ड स्तर तक सूक्ष्म-स्तर का डेटा प्राप्त किया जाता है।
- पिछली जनगणना: विगत जनगणना 2011 में की गई थी। 2021 की जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।

लोक सभा में "कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अमृत मिशन (अमृत/AMRUT)" पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

इस रिपोर्ट में अमृत मिशन के क्रियान्वयन के दौरान सामने आई प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। साथ ही, इस मिशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं।

अमृत मिशन के बारे में

- क्रियान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
- योजना का प्रकार: केन्द्र प्रायोजित योजना
- योजना का उद्देश्य: चयनित शहरों एवं कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेंज एवं सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र एवं पार्क, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के लिए मूलभूत शहरी अवसंरचनाओं का विकास।

अमृत मिशन के क्रियान्वयन में मुख्य चुनौतियां एवं सिफारिशें

विषय-क्षेत्र	मुख्य चुनौतियां	सिफारिशें
वित्त-पोषण एवं वित्तीय क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> अवसंरचना के लिए अपर्याप्त वित्तपोषण; अवसंरचनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए निधि की कमी तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों की कमी। 	<ul style="list-style-type: none"> विशेषकर पिछड़े/कम सेवा-प्राप्त क्षेत्रों में केंद्रीय एवं बहुपक्षीय वित्तीय सहायता को बढ़ाया जाए। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और नगरपालिका बांड (म्युनिसिपल बॉण्ड) जैसे नए वित्त-पोषण स्रोतों का उपयोग किया जाए।
क्रियान्वयन एवं संस्थागत ढांचा	<ul style="list-style-type: none"> क्रियान्वयन की धीमी गति: अमृत 2.0 के अंतर्गत 1.90 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, किंतु केवल लगभग 48,050 करोड़ रुपये की अवसंरचनाएं ही पूरी हो पाई हैं। शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की सीमित भूमिका: मिशन के क्रियान्वयन में अर्ध-सरकारी संस्थाओं का वर्चस्व रहा है। एकीकृत जल प्रबंधन एवं दीर्घकालिक रणनीति का अभाव है। 	<ul style="list-style-type: none"> शहरी स्थानीय निकायों की संस्थागत एवं तकनीकी क्षमता निर्माण हेतु एक राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया जाए। सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहरी जल कार्य-योजना (City Water Action Plans: CWAPs) का 100% प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाए। दीर्घकालिक योजना-बनाना: अगले 25-30 वर्षों के लिए शहरी पेयजल मांग का राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत आकलन एवं पूर्वानुमान शीघ्र कराया जाए। विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के बीच समन्वय (convergence) को सख्ती से लागू किया जाए।
तकनीकी, परिचालन एवं निगरानी में जुड़े मुद्दे	<ul style="list-style-type: none"> जलापूर्ति वाले क्षेत्र, जलापूर्ति प्रणाली में होने वाले नुकसान (नॉन-रेवेन्यू वाटर), वाटर मीटरिंग एवं अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से संबंधित डेटा को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अपशिष्ट जल (सीवेज) का बड़ा हिस्सा अनुपचारित: शहरी भारत में कुल सीवेज उत्पादन लगभग 48,004 मिलियन लीटर दैनिक (MLD) था जबकि स्थापित उपचार क्षमता लगभग 30,001 MLD (2021) थी। 	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय शहरी अपशिष्ट जल पुनः उपयोग नीति तैयार की जाए। अपशिष्ट जल उपचार क्षमता बढ़ाई जाए एवं इसके पुनः उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाए। जलापूर्ति प्रणाली में होने वाले नुकसान (नॉन-रेवेन्यू वाटर) में कमी के लिए प्रोत्साहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा स्मार्ट मीटरिंग की स्थापना में तेजी लाई जाए।

UNEA-7 में भारत के वनाग्नि से संबंधित एक संकल्प को अपनाया गया

नैरोबी (केन्या) में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र (UNEA-7) संपन्न हुआ। इस सत्र में भारत के 'वनाग्नि के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना' (Strengthening the Global Management of Wildfires) शीर्षक से एक संकल्प को अपनाया गया है।

- इस संकल्प का उद्देश्य वनाग्नि के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्रवाई को मजबूत करना है।
- UNEA-7 में कुल 11 संकल्प पारित किए गए हैं। इनमें प्रवाल भित्तियों (coral reefs), रोगाणुरोधी प्रतिरोध (antimicrobial resistance), हिमांकमंडल (cryosphere), रसायन, अपशिष्ट आदि से संबंधित संकल्प शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 'स्मेटिंग लाइव वाइल्डफायर' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहे, तो 2100 तक वनाग्नि में 50% की वृद्धि हो सकती है।

भारत के संकल्प के प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना: पूर्व-चेतावनी प्रणालियों, जोखिम आकलन, उपग्रह व भूमि आधारित निगरानी प्रणालियों और सामुदायिक चेतावनी तंत्र का विकास करना चाहिए।
- क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग में वृद्धि: वनाग्नि रोकथाम, प्रतिक्रिया के बाद पुनर्प्राप्ति और पारिस्थितिकी-तंत्र की बहाली का समर्थन करने वाले तंत्रों का विकास करना चाहिए।
- ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण: सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों के लिए मंचों का निर्माण करना चाहिए।
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्य योजनाओं के लिए समर्थन: एकीकृत आगजनी प्रबंधन और वनाग्नि से निपटने की अनुकूलन रणनीतियों के लिए सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।
- वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना: बहुपक्षीय और परिणाम-आधारित वित्त-पोषण के लिए परियोजना तैयारी में मदद करनी चाहिए।

भारत में वनाग्नि की वर्तमान स्थिति

- भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR), 2019 के अनुसार, देश के 36% से अधिक वन बार-बार वनाग्नि की चपेट में आते हैं, लगभग 4% अत्यधिक वनाग्नि प्रवण हैं, और 6% बहुत अधिक अग्नि-प्रवण पाए गए हैं।
- उपग्रह-आधारित रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी और GIS उपकरण (जैसे- MODIS सेंसर एवं SNPP-VIIRS) वनाग्नि की बेहतर रोकथाम व प्रबंधन में प्रभावी रहे हैं।
 - MODIS: मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो-रेडियोमीटर।
 - SNPP-VIIRS: सुओमी-नेशनल पोलर-ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप- विजिबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) के बारे में

- मुख्यालय: नैरोबी (केन्या)।
- स्थापना: इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन में स्थापित किया गया था।
- भूमिकाएं और कार्य:
 - यह पर्यावरण से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
 - यह वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है; नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा विश्व में उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाओं को परिभाषित करता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI)" विधेयक को मंजूरी दी

शांति/SHANTI विधेयक 2025 का उद्देश्य परमाणु विद्युत उत्पादन में विनियमित रूप में निजी क्षेत्र को प्रवेश देना है।

SHANTI विधेयक 2025 की प्रमुख विशेषताएं

- परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी: परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की मूल्य-श्रृंखला (वैल्यू चेन) के सभी चरणों में निजी कंपनियों को प्रवेश देने का प्रस्ताव किया गया है। इससे भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) का विशिष्ट एकाधिकार समाप्त होगा।
- एकीकृत कानूनी ढांचा: परमाणु ऊर्जा के विकास से जुड़े वर्तमान कानूनों को एक ही विस्तृत अधिनियम में समाहित किया जाएगा। इससे विनियामकीय स्पष्टता बढ़ेगी और निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा।

भारत में परमाणु ऊर्जा विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी का महत्व

- संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी: निजी क्षेत्र की भागीदारी से पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी तथा देश एवं विदेश से निवेश आकर्षित होगा। इससे वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।
- प्रौद्योगिकी में नवाचार (इनोवेशन) को बढ़ावा मिलेगा: निजी क्षेत्र के प्रवेश से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs), मॉड्यूलर रिएक्टर डिज़ाइन और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी आएगी।
- ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी: निजी क्षेत्र की भागीदारी से परमाणु ऊर्जा उत्पादन, संयंत्र विनिर्माण और आपूर्ति-श्रृंखला को बढ़ावा मिलेगा तथा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी।

निजी क्षेत्र की भागीदारी से जुड़ी चुनौतियां

- रिएक्टर की सुरक्षा एवं दुर्घटना के दायित्व से संबंधित मुद्दे: 'परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम (CLNDA), 2010' के तहत परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के संबंध में दायित्व पर सख्त प्रावधान हैं। इससे परमाणु ऊर्जा उपकरणों के निजी क्षेत्र के आपूर्तिकर्ता और निवेशक हतोत्साहित हो सकते हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा: परमाणु ऊर्जा उत्पादन में अति-सुरक्षित पदार्थों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। इसमें निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने से पहले कड़े सुरक्षा उपायों तथा आपूर्ति श्रृंखला (ट्रेसिबिलिटी) पर गहन निगरानी की आवश्यकता होगी।
- दीर्घकालिक परियोजना अवधि: परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिज़ाइन से लेकर पूर्ण होने में सामान्यतः 7 से 10 वर्ष लगते हैं। व्यवहार्यता अंतराल निधि (Viability Gap Funding) या जोखिम-साझेदारी तंत्र के न होने से निवेशकों की रुचि कम हो सकती है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर संसदीय पैनल ने रिपोर्ट जारी की

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की।

विषय	रिपोर्ट की मुख्य टिप्पणियां	रिपोर्ट की सिफारिशें
वायु गुणवत्ता मानक और निगरानी	<ul style="list-style-type: none"> WHO के दिशा-निर्देश सलाहकारी प्रकृति के हैं, न कि प्रवर्तनीय। वर्तमान NAAQS (राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक) को अंतिम बार 2009 में संशोधित किया गया था। 	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल मानक निर्धारित करने चाहिए। NAAQS को संशोधित करना चाहिए। सभी क्षेत्रों में लगभग नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
वाहनों से उत्सर्जन	<ul style="list-style-type: none"> प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत वाहन हैं। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन अभी भी चल रहे हैं। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की वाष्पशीलता (volatility) से वाष्पीकरण उत्सर्जन बढ़ता है। इससे ओजोन निर्माण को बढ़ावा मिलता है। 	<ul style="list-style-type: none"> PUCC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र) प्रवर्तन को मजबूत करना चाहिए। उपयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को स्कैपेज के माध्यम से चरणबद्ध रीति से समाप्त करना चाहिए। वाहन द्वारा उत्सर्जन मानकों की समीक्षा करनी चाहिए।
पराली दहन	<ul style="list-style-type: none"> शीतकाल में फसल अवशेष जलाना सर्दियों में प्रदूषण को और बढ़ाता है। दहन से इतर फसल अवशेष प्रबंधन में किसानों को समय और लागत संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 	<ul style="list-style-type: none"> खेत में और खेत के बाहर फसल अवशेष प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए। जिला स्तर पर सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्यों के मध्य समन्वय में सुधार करना चाहिए।
औद्योगिक प्रदूषण	<ul style="list-style-type: none"> कुछ उद्योगों में अस्वच्छ ईंधन का उपयोग जारी है। लघु और असंगठित इकाइयों की निगरानी कमजोर है। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> उद्योगों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। जो इकाइयां नियमों का अनुपालन नहीं करती हैं, उन्हें बंद करना चाहिए। पेट कोक जैसे अवैध ईंधनों पर अंकुश लगाना चाहिए। ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों का विस्तार करना चाहिए।
दिल्ली में वनीकरण	<ul style="list-style-type: none"> दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का केवल 13% ही वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र में आक्रामक प्रजातियों की उपस्थिति पारिस्थितिक मूल्य को कम करती है। 	<ul style="list-style-type: none"> वनीकरण को महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसरों के रूप में मान्यता देनी चाहिए। मियावाकी पद्धति अपनानी चाहिए। <ul style="list-style-type: none"> मियावाकी विधि सीमित क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देती है। आक्रामक प्रजातियों को हटाकर देशज प्रजातियों को बढ़ावा देना चाहिए।



अन्य सुर्खियां



पैक्स सिलिका पहल

‘पैक्स सिलिका’ संयुक्त राज्य अमेरिका की नई महत्वपूर्ण खनिज विविधीकरण योजना है। भारत को इस योजना से बाहर रखा गया है।

पैक्स सिलिका पहल के बारे में

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली एक रणनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित, समृद्ध एवं नवाचार-संचालित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। इसमें महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा इनपुट से लेकर उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, AI अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स तक शामिल होंगे।
- लक्ष्य: निर्भरताओं को कम करना। साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि संबंधित राष्ट्र परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर विकसित और उपयोग कर सकें।
- सदस्य: जापान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया।



राष्ट्रीय मखाना बोर्ड

हाल ही में, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मखाना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ₹476 करोड़ की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई।

- साथ ही, अनुसंधान, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन, मूल्य संवर्धन और निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक रोडमैप को भी मंजूरी दी गई।

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के बारे में

- मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है।
- लक्ष्य: मखाना क्षेत्र के मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और वैश्विक स्थिति को बढ़ावा देना।
- अवस्थिति: बिहार।
- उद्देश्य: किसानों की आय में सुधार करना तथा वैज्ञानिक खेती, तालाबों से निकालने के बाद के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।



IFAD

भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD)-भारत दिवस पर ग्रामीण परिवर्तन और विकास नेतृत्व पर प्रकाश डाला।

IFAD के बारे में

- मुख्यालय: रोम (इटली)।
- संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी: IFAD एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। यह ग्रामीण गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने के प्रति समर्पित है।
- लघु जोत पर ध्यान: यह वित्त, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लघु जोत वाले किसानों, चरवाहों एवं ग्रामीण उद्यमियों का समर्थन करता है।
- ग्रामीण विकास वित्त-पोषण: यह कृषि, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, मूल्य-श्रृंखला विकास और आजीविका विविधीकरण के लिए ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है।



राज्यों में असमान डिजिटल प्रगति

हाल ही में, ICRIER-Prosus सेंटर ने एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारतीय राज्यों में डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण असमानताओं को उजागर करती है। इनमें से कुछ राज्य तेजी से प्रगति कर रहे हैं, जबकि अन्य पीछे छूट रहे हैं।

- ICRIER: अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद।
- Prosus यूरोप की एक कंपनी है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- यह रिपोर्ट उप-राष्ट्रीय स्तर पर असमान डिजिटल परिवर्तन को उजागर करती है। इसमें राज्य विभिन्न गति से प्रगति कर रहे हैं।
- डिजिटलीकरण स्कोर में दिल्ली शीर्ष पर है। इसके बाद केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा हैं।
- झारखंड जैसे राज्य बहुत नीचे हैं। यह असमानता डिजिटलीकरण में राज्यों के मध्य व्यापक अंतर को दर्शाती है।
- यदि पिछड़े राज्य गति नहीं पकड़ पाते हैं, तो भारत के महत्वाकांक्षी डिजिटल भारत लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।



मेवेन (MAVEN) अंतरिक्ष यान

NASA का मंगल की कक्षा में मौजूद मेवेन अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया।

MAVEN (मार्स अट्मोस्फियर एंड वोलेटाइल एक्सप्लोरेशन) अंतरिक्ष यान के बारे में

- प्रक्षेपण: वर्ष 2013 में NASA द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
- उद्देश्य: मंगल के ऊपरी वायुमंडल व आयनोस्फीयर और सूर्य एवं सौर पवनों के साथ इनकी अभिक्रिया का पता लगाना। इससे मंगल के वायुमंडल के अंतरिक्ष में लुप्त होने का पता लगाया जा सकेगा।



कोलसेतु नीति (CoalSETU Policy)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला लिंकेज (कोलसेतु/ CoalSETU) की नीलामी नीति को मंजूरी प्रदान की।

कोलसेतु नीति के बारे में:

- यह 2016 की गैर-विनियमित क्षेत्र (NRS) लिंकेज नीलामी नीति के तहत कोयले के लिए एक नई नीलामी विंडो बनाती है।
- उद्देश्य: किसी भी तरह के औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए नीलामी के आधार पर कोयला लिंकेज का दीर्घकालिक आवंटन करने की अनुमति प्रदान करना।
- अपवाद: कोकिंग कोयले को इस विंडो के तहत प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
- भागीदारी: कोयले की आवश्यकता वाला कोई भी घरेलू खरीदार लिंकेज नीलामी में भाग ले सकता है।
 - ⊙ व्यापारियों को इस विंडो के तहत बोली लगाने की अनुमति नहीं है।
- प्राप्त कोयले का उपयोग:
 - ⊙ खरीदार द्वारा स्वयं उपभोग।
 - ⊙ कोयले का निर्यात (लिंकेज मात्रा का 50% तक)।
 - ⊙ कोयला धुलाई या नीति के तहत अनुमत अन्य उद्देश्य।
 - ⊙ अपवाद: देश में पुनर्विक्रय (Resale) की अनुमति नहीं है।



ग्रीह विहियर मंदिर

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा संघर्ष के बीच भारत ने ग्रीह विहियर मंदिर की सुरक्षा का आह्वान किया।

ग्रीह विहियर मंदिर के बारे में

- अवस्थिति: कंबोडिया में (थाईलैंड से सटी सीमा के निकट)।
- प्रधान देवता: यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।
- इतिहास: इस मंदिर का निर्माण खमेर राजवंश के राजा यशोवर्मन प्रथम (889-910 ईस्वी) ने आरंभ कराया था तथा राजा सूर्यवर्मन द्वितीय (1113-1150 ईस्वी) के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था।
- यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।



PMGKY पैकेज: स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना

उच्चतम न्यायालय ने “प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना” के तहत कोविड ड्यूटी में जान गंवाने वाले सभी चिकित्सकों को ₹50 लाख के बीमा के दायरे अंतर्गत लाने का निर्देश दिया।

“प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना” के बारे में

- उद्देश्य: कोविड-19 ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- कार्यान्वयन मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- बीमा कवरेज: प्रति लाभार्थी ₹50 लाख का दुर्घटना बीमा कवर।
- कवरेज का दायरा:
 - ⊙ ड्यूटी के दौरान कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु; तथा
 - ⊙ कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी करते समय आकस्मिक मृत्यु।
- लाभार्थी: डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स और सहायक कर्मचारियों सहित कोविड-19 ड्यूटी में प्रत्यक्ष रूप से शामिल स्वास्थ्य सेवा कर्मी।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर